



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 495]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 19, 2005/वैशाख 29, 1927

No. 495]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 19, 2005/VAISAKHA 29, 1927

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मई, 2005

का०आ० 680(अ).—मेघालय के अचीक नेशनल वालंटियर कौंसिल (एएनवीसी) और हन्नीवट्रेप लिब्रेशन कौंसिल (एचएनएलसी) नामक संगठनों को विधिविरुद्ध घोषित किए जाने के लिए पर्याप्त कारण विद्यमान होने अथवा न होने के संबंध में न्याय-निर्णयन के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता में गठित अधिकरण को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 4(1) के अधीन भेजे गए संदर्भ के संबंध में पारित उनके आदेश को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 4(4) के अनुसरण में आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

माननीय न्यायमूर्ति श्री स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता में गठित  
विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण  
के समक्ष प्रस्तुत मामला

12-05-2005

मामला : मेघालय के अचीक नेशनल वालंटियर कौंसिल और हन्नीवट्रेप नेशनल लिब्रेशन कौंसिल को विधिविरुद्ध संगम घोषित करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II खंड-3, उपखंड (ii) में दिनांक 16-11-2004 को प्रकाशित भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1266 (अ)।

**आदेश**

गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 16 नवम्बर, 2004 को निम्नलिखित अधिसूचना जारी की :-

**भारत सरकार**

**गृह मंत्रालय**

\* \* \* \*

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, दिनांक 16 नवम्बर, 2004

**का.आ. 1266 (अ)** यंतः मेघालय के अचीक नेशनल वालंटियर कौंसिल (जिसे इसमें इसके पश्चात 'एएनवीसी' कहा गया है) ने हिंसा छोड़ने पर सहमत होने तथा अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए भारत के संविधान के दायरे में वार्ता करने की इच्छा व्यक्त करने के बावजूद धन संग्रह करना और जबरन धन वसूलना, अत्याधुनिक हथियार प्राप्त करना तथा नए कार्यकर्ताओं की भर्ती करना जारी रखा है;

और यतः, मेघालय का हन्नीवट्रेप नेशनल लिब्रेशन कौंसिल (जिसे इसमें इसके बाद एचएनएलसी कहा गया है) ने :

- (i) मेघालय को भारत संघ से अलग करने के अपने उद्देश्य की खुलेआम घोषणा की है;
- (ii) अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सशस्त्र साधनों का उपयोग जारी रखा है;

- (iii) अपने संगठन के लिए धन संग्रह हेतु नागरिकों को डराना-धमकाना, उनसे धन ऐंठना और उन्हें लूटना जारी रखा है;

और यतः एएनवीसी तथा एचएनएलसी दोनों :

- (i) शस्त्र एवं गोलाबारूद प्राप्त करने के लिए तथा हिंसा, जबरन धन वसूली, डराने-धमकाने एवं लूटपाट के कार्य करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य विद्रोही गुटों के साथ संपर्क बनाए हुए हैं;
- (ii) आश्रय, प्रशिक्षण तथा चोरी छुपे शस्त्र एवं गोलाबारूद प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए कुछ पड़ोसी देशों में शिविर स्थापित किए हुए हैं;

और यतः केन्द्रीय सरकार का मत है कि उपरोक्त कारणों से एएनवीसी और एचएनएलसी और उनके द्वारा गठित अन्य निकाय विधिविरुद्ध संगम है।

और यतः केन्द्रीय सरकार का भी यह मत है कि अचीक नेशनल वालंटियर कौंसिल (एएनवीसी) और हन्नीवट्रेप नेशनल लिब्रेशन कौंसिल (एचएनएलसी) की उपरोक्त गतिविधियां भारत की प्रभुसत्ता और अखण्डता को विच्छिन्न करने के लिए आशयित है और यदि इन पर तत्काल नियंत्रण न किया गया तो ये संगठन पुनर्संगठित होंगे, पुनः शस्त्रों से लैस होंगे, अपने कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाएंगे, अत्याधुनिक हथियार प्राप्त करेंगे, भारी संख्या में नागरिकों और सुरक्षा बलों की हत्या करेंगे और मेघालय को भारत से विलग करने के अपने उद्देश्य के लिए अपनी गतिविधियां बढ़ाएंगे।

अतः, अब, विधिविरुद्ध गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, अचीक नेशनल वालंटियर कौंसिल (एएनवीसी) और हन्नीवट्रेप नेशनल लिब्रेशन कौंसिल (एचएनएलसी) को इनके सभी गुटों, विंगों और मुख्य संगठनों सहित विधिविरुद्ध संगम घोषित करती है।

केन्द्रीय सरकार का भी यह मत है कि अचीक नेशनल वालंटियर कौंसिल (एएनवीसी) और हन्नीवट्रेप नेशनल लिब्रेशन कौंसिल (एचएनएलसी) को इनके सभी गुटों, विंगों और मुख्य संगठनों सहित तत्काल प्रभाव से विधिविरुद्ध संगम घोषित करना आवश्यक है, और तदनुसार धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, निदेश देती है

कि यह अधिसूचना उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन किए जा सकने वाले किसी आदेश के अधीन सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होगी ।

[फा0सं0 11011/47/2004-एन0ई0-III]

(एच0एस0 ब्रह्मा)  
संयुक्त सचिव, भारत सरकार"

केन्द्रीय सरकार ने 15 दिसम्बर, 2004 के "विधि विरुद्ध कार्यकलाप (निवारण) अधिनियम", 1967 (जिसे इसमें इसके बाद अधिनियम कहा है) की धारा 5 (1) के अधीन अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में एक "विधिविरुद्ध कार्यकलाप निवारण अधिकरण" का गठन किया और उक्त अधिसूचना इस अधिकरण को यह न्याय-निर्णय करने के लिए भेजी कि उक्त संगम को "विधिविरुद्ध" संगम घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण मौजूद हैं अथवा नहीं। इससे पूर्व कि मैं दिनांक 16 नवम्बर, 2004 को उक्त अधिसूचना के संबंध में आरोपों, साक्ष्य और विधिक पहलुओं पर चर्चा करूं, इस रिपोर्ट के शुरू में दी गई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का उल्लेख करना उपयोगी हो सकता है।

यह बताया गया है कि अचीक नेशनल वालंटियर कौंसिल (जिसे इसमें इसके पश्चात 'ए एन वी सी' कहा गया है) तथा हन्नीवट्रेप नेशनल लिब्रेशन कौंसिल (जिसे इसमें इसके पश्चात 'एच एन एल सी' कहा गया है) को इस अधिनियम के प्रासंगिक उपबंधों के अन्तर्गत दिनांक 16 नवम्बर, 2004 की अधिसूचना के तहत 'विधिविरुद्ध संगम' घोषित किया गया है। इससे पूर्व, केन्द्र सरकार द्वारा गठित अधिकरण को एक पत्र लिखा गया था तथा इस अधिकरण ने दिनांक 16 नवम्बर, 2002 की अधिसूचना के तहत केन्द्र सरकार द्वारा की गई घोषणा की पुष्टि की थी। केन्द्र एवं संबंधित राज्य सरकारों का मामला यह है कि दिसम्बर, 1995 में ए एन वी सी का गठन किया गया था जिसका उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, गैर जनजातियों की घुसपैठ तथा गारो लोगों के शोषण को रोकने के लिए नए

‘अचीक लैण्ड’ राज्य के गठन हेतु गारो हिल्स को मुक्त कराना था। इस बात का दृढ़तापूर्वक उल्लेख किया जाता है कि ए एन वी सी हिंसा का त्याग करने के लिए सहमत हो गई थी तथा उन्होंने अपनी मांगों को पूरा करने के लिए भारत के संविधान के ढांचे के भीतर बातचीत करने की अपनी इच्छा व्यक्त की है, किन्तु ए एन वी सी के काडरों ने व्यवसायियों, ठेकेदारों तथा आम जनता से जबरन धन वसूली जारी रखी। वे अपने संगठनों में नए काडरों की भर्ती भी कर रहे हैं।

एच एन एल सी के बारे में यह बताया जाता है कि इसका गठन 1992 में हन्नीवट्रेप लोगों को भारत सरकार के शासन से मुक्त कराने, खासी लोगों तथा मेघालय की अन्य जनजातियों को कथित शोषण से बचाने, स्थानीय संस्कृति को बनाए रखने तथा सामाजिक बुराईयों को समाप्त करने के उद्देश्य से किया गया था। उनका मूल उद्देश्य मेघालय राज्य को भारत से अलग कराना है। एच एन एल सी ने अपनी मांगों को पूरा करने के लिए हिंसा का त्याग करने तथा संविधान के दायरे में रहकर बातचीत करने की अपनी इच्छा व्यक्त नहीं की है। इस संगठन के पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य विद्रोही संगठनों के साथ संबंध हैं। इनके अन्य विधिविरुद्ध क्रियाकलापों में व्यवसायियों तथा आम जनता से जबरन धन वसूली करना शामिल है।

ए एन वी सी गारो हिल्स जिलों, विशेष रूप से पूर्वी गारो हिल्स में सक्रिय है। इसके काडर बंगलादेश में नेशनल सोशलिस्ट कौंसिल ऑफ नागालैण्ड (एन एस सी एन) के शिविरों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी सूचना है कि इस संगठन के बड़े काडर बंगलादेश में ठहरे हुए हैं, जबकि एच एन एल सी मुख्य रूप से शिलांग सिटी तथा पूर्वी खासी हिल्स, पश्चिमी खासी हिल्स और रि-मोई जिलों के कुछ क्षेत्रों में सक्रिय है। एच एन एल सी ने बंगलादेश में भी कुछ अड्डे, आश्रय एवं प्रशिक्षण शिविर स्थापित कर लिए हैं।

अध्यक्ष/कमाण्डर-इन-चीफ सहित इसके कुछ बड़े सदस्य बंगलादेश में रहे हैं। ए एन वी सी

1554 GI/05-2

के काडरों की कुल संख्या 25 है तथा इस संगठन के पास कुल 70 हथियार होने का अनुमान है। इसके काडर तथा हथियारों की संख्या का बड़ा भाग अभी भी भूमिगत है तथा उच्च नेता बंगलादेश में छिपे हुए हैं। इस संगठन की प्रहार क्षमता को अभी तक निष्क्रिय नहीं किया गया है। यह एक विशिष्ट बात है कि ए एन वी सी, एन एस सी एन के साथ गहन संबंध बनाए हुए हैं जो शस्त्र एवं गोला बारूद जुटाने, काडरों के प्रशिक्षण और संयुक्त अभियानों में भी इसकी सहायता कर रही है। यह संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) तथा नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एन डी एफ बी) के साथ भी संबंध बनाए हुए है। वर्ष 2001-2002 के दौरान हत्याओं, लूटपाट तथा सुरक्षा बल कर्मिकों पर हिंसक हमले जैसी हिंसा की घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है। 23 जुलाई, 2004 को भारत सरकार, मेघालय सरकार और ए एन वी सी द्वारा अभियान को निलंबित रखने संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। यद्यपि युद्धविराम के समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद कोई हत्या नहीं की गई है, किंतु अन्य गतिविधियां पूरी तरह से बंद नहीं हुई हैं और यदि प्रतिबंध हटाया जाता है एवं विद्रोह विरोधी अभियानों में कोई ढील दी जाती है तो इस बात की पूरी संभावना है कि ए एन वी सी और भी अधिक सक्रिय हो जाएगी।

विद्रोह विरोधी अभियानों के कारण वर्ष 2003 में एच एन एल सी की हिंसा में कमी आई थी और 74 भूमिगत लोगों ने आत्म समर्पण किया था जिसकी वजह से विशेष रूप से शिलांग में हिंसक गतिविधियों में काफी कमी आई। अनेक गिरफ्तारियां की गईं तथा सशस्त्र मुठभेड़ में 12 ए एन वी सी उग्रवादी मारे गए। इन विधिविरुद्ध संगमों के विधिविरुद्ध क्रियाकलापों को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय मेघालय सरकार, रक्षा मंत्रालय, सेना मुख्यालय, आसूचना ब्यूरो, अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग (रॉ), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और सीमा रिजर्व बल के विचार मांगे गए थे। सेना मुख्यालय तथा रक्षा मंत्रालय ने एक दूसरे के विचारों से सहमति जताते हुए 15 नवम्बर, 2004 से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रतिबंध को बढ़ाने की सिफारिश की। तथापि, आसूचना ब्यूरो के अनुसार ये गुट अभी भी

हिंसा के मार्ग में विश्वास रखते हैं, इसलिए प्रतिबंध नहीं हटाया जाना चाहिए। अन्य प्राधिकारियों ने भी इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंध जारी रखने की सिफारिश की कि पिछले एक वर्ष के दौरान ये गुट मेघालय में अनेक विद्रोही गतिविधियों में और व्यवसायियों, ठेकेदारों और आम व्यक्तियों से धन ऐंठने में संलिप्त रहे और दोनों गुटों ने अपने विद्रोही क्रियाकलाप जारी रखे और मेघालय में तथा सीमापार बंगलादेश में शिविरों में अपने संवर्गों को छोटे हथियारों के इस्तेमाल और छापामार युद्ध का प्रशिक्षण देना जारी रखा।

दिनांक 16 नवंबर, 2004 और 15 दिसम्बर, 2004 की अधिसूचनाएं जारी किए जाने के बाद अधिकरण ने पहली सुनवाई 6 जनवरी, 2005 को नई दिल्ली में की। उस दिन यह निर्देश दिया गया कि समाचार पत्रों में प्रकाशन के जरिए तथा 18 फरवरी, 2005 के आदेश में दिए गए निर्देशों के अनुरूप उक्त संगठनों को नोटिस जारी किए जाएं। श्री आर० आर० झा, निदेशक, भारत सरकार, गृह मंत्रालय का एक शपथ पत्र दायर किया गया जिसमें यह कहा गया कि चार स्थानीय समाचार पत्रों अर्थात् दिनांक 13 जनवरी, 2005 के 'द टेलीग्राफ कोलकाता' में 12 जनवरी, 2005 के 'द शिलांग टाइम्स' 12 जनवरी, 2005 के 'द यू माफोर' और 13 जनवरी, 2005 के 'सालेंतिनी जानेरा' में नोटिस प्रकाशित हुए। शपथ पत्र के साथ, रिकार्ड के लिए संगत समाचार पत्रों की कटिंग की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई हैं। उक्त शपथ पत्र में यह भी कहा गया है कि मेघालय सरकार के अनुसार, नोटिसों को 12 जनवरी, 2005 को दूरदर्शन केन्द्र, शिलांग के 'सिटी स्कैन' कार्यक्रम में प्रसारित किया गया था और 12 जनवरी, 2005 को आकाशवाणी के शिलांग स्टेशन के जरिए प्रसारित किया गया था और इसके अलावा नोटिसों को सार्वजनिक स्थानों पर चिपकाया गया और मेघालय राज्य के सभी सात जिलों के उपायुक्तों के नोटिस बोर्डों पर भी लगाया गया। उक्त शपथ पत्र के संबंध में यह बताया जाता है कि इन संगठनों को नोटिस सीधे तौर पर नहीं दिए जा सकते थे क्योंकि उनका कोई निर्धारित ठिकाना नहीं है और प्रशासन को उसकी जानकारी नहीं है। नोटिस दिए जाने के तरीके से संतुष्ट होकर अधिकरण ने यह निर्देश दिया

था कि मामले की सुनवाई इन संगठनों की गैर-मौजूदगी में भी की जाए क्योंकि समाचार पत्रों में प्रकाशन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से नोटिस का व्यापक प्रचार किए जाने के बावजूद इन संगठनों की ओर से कोई भी व्यक्ति पेश नहीं हुआ। अधिनियम की धारा 5(5) और 5(6) के अंतर्गत किए गए विचार के अनुसार, अधिनियम के उपबंधों के तहत जांच करते समय अधिकरण के पास ये शक्तियां होंगी कि वह अपने कार्यों के निपटान से उठे सभी मामलों में अपनी प्रक्रिया को विनियमित करे और उसके पास सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत सिविल न्यायालय में यथानिहित वहीं शक्तियां होंगी। अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत रिकार्ड से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि गैर-कानूनी संगठनों को उक्त माध्यमों से पर्याप्त रूप से नोटिस दिए गए और उन्हें न्याय हेतु, अधिकरण के समक्ष पेश होने के पर्याप्त अवसर प्रदान किए गए हैं। विधिवत रूप से नोटिस दिए जाने के बावजूद पेश न होने के कारण यह आदेश दिया गया कि संबंधितों की गैर-मौजूदगी में कार्यवाही जारी रखी जाए।

दिनांक 28 फरवरी, 2005 को श्री आर0 आर0 झा के शपथ पत्र को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। उनको जिरह का अवसर दिया गया। चूंकि उनसे जिरह के लिए कोई भी उपस्थित नहीं हुआ इसलिए शपथ पत्र को रिकार्ड में ले लिया गया। मेघालय राज्य की ओर से पेश अधिवक्ता के अनुरोध पर उन्हें मेघालय राज्य की ओर से शपथ-पत्र दायर करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया। उसके बाद शिलांग में साक्ष्य की रिकार्डिंग के लिए मामले की तारीख 30 और 31 मार्च, 2005 निर्धारित की गई क्योंकि अधिसूचना के समर्थन में उस क्षेत्र से अनेक गवाहों से पूछताछ की जानी थी। दिनांक 30 मार्च, 2005 को अधिकरण ने निम्नलिखित आदेश दिया:-

" अधिकरण की कार्यवाही यथानिर्धारित प्रातः 10.30 बजे शुरू हुई।



अधिकरण के आदेश के अनुसार नोटिसों को समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया गया और उपयुक्त स्थानों पर चिपकाया गया। पूर्व आदेश के अनुसार नोटिस दिए जाने के सबूत भी न्यायालय में प्रस्तुत किए गए हैं। विधिवत रूप से नोटिस दिए जाने के बावजूद दोनों कथित गैर-कानूनी संगमों अर्थात् एएनवीसी और एचएनएलसी की ओर से कोई भी व्यक्ति पेश नहीं हुआ। नई दिल्ली में पूर्व तिथि अर्थात् 18.2.2005 को हुई सुनवाई में भी उनकी ओर से कोई व्यक्ति पेश नहीं हुआ। चूंकि आज भी उनकी ओर से कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं हुआ इसलिए अधिकरण मामले पर कानून के अनुसार तथा उनकी अनुपस्थिति में कार्यवाही करेगा।

मेघालय राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील ने राज्य की ओर से पूछताछ किए जाने वाले गवाहों की सूची प्रस्तुत की है। सूची में उल्लिखित 15 गवाहों में से राज्य का केवल 10 गवाहों से ही पूछताछ करने का प्रस्ताव है। उन्होंने यह भी बताया है कि आयुक्त-सह-सचिव, मेघालय सरकार, राजनीतिक विभाग ने साक्ष्य के रूप में एक शपथ पत्र पहले ही दायर कर दिया है। वह न्यायालय में उपस्थित हैं और अनुरोध करती हैं कि उनके बयान को भी रिकार्ड किया जाए। आयुक्त-सह-सचिव और अन्य गवाहों का बयान भी रिकार्ड होने दिया जाए।"

तदनुसार, सीडब्ल्यू-1 से सी डब्ल्यू-10 तक 10 गवाहों के बयान रिकार्ड किए गए। इन सभी गवाहों को जिरह के लिए प्रस्तुत किया गया लेकिन शिलांग में भी कथित गैर-कानूनी संगठनों की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ इसलिए गवाहों को मुक्त कर दिया गया। मेघालय राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील ने राज्य की ओर से अपने साक्ष्य की कार्यवाही बंद कर दी। तथापि, भारत संघ की ओर से पेश वकील ने अनुरोध किया था कि श्री आर० आर० झा का बयान भी रिकार्ड किया जाए, हालांकि उनका शपथ पत्र पहले ही साक्ष्य में प्रस्तुत किया जा चुका था। यह भी अनुरोध किया गया कि श्री झा का बयान नई दिल्ली में रिकार्ड किया जाए क्योंकि वह अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण शिलांग में उपस्थित नहीं हो सकते। वकील का अनुरोध स्वीकार कर लिया गया और श्री आर० आर० झा से पूछताछ और दूसरी कार्यवाही के लिए नई दिल्ली में मामले की तारीख 11 अप्रैल, 2005 निर्धारित की गई। 11 अप्रैल, 2005 को श्री आर० आर० झा का बयान दर्ज किया गया। यह मामला 15

15.04.05 GI/05-3.

अप्रैल, 2005, 21 अप्रैल, 2005 तथा अन्ततः 3 मई, 2005 को सुनवाई के लिए नियत किया गया जब दलीलों पर निष्कर्ष निकाला गया तथा मामलों को आदेशों के लिए आरक्षित रखा गया।

इस अधिसूचना के समर्थन में श्री आर० आर० झा का हलफनामा पांच अनुलग्नकों के साथ दायर किया गया। हलफनामे में यह बताया गया है कि एएनवीसी निधियों के सतत संग्रहण और व्यापारी वर्ग, ठेकेदारों तथा आम जनता से धन ऐंठने, अत्याधुनिक हथियार प्राप्त करने तथा इस गुट द्वारा हिंसा का परित्याग करने और अपनी मांगें पूरी कराने के लिए भारत के संविधान के ढांचे के अंतर्गत वार्ता करने की अपनी इच्छा व्यक्त करने के बावजूद एएनवीसी नए काडरों की भर्ती करने में लगा हुआ है। हलफनामे में आगे यह भी बताया गया है कि एचएनएलसी का उद्देश्य हन्नीवट्रेप लोगों की आजादी, मेघालय राज्य का भारत से प्रथक्करण करना अब भी बना हुआ है तथा एचएनएलसी ने हिंसा का परित्याग करने तथा वार्ता करने की अपनी इच्छा व्यक्त नहीं की है। इस बात का विशेष और स्पष्ट उल्लेख है कि एएनवीसी काडर बंगलादेश में एएससीएन शिविरों में प्रशिक्षण प्राप्त रहे हैं और ऐसी सूचना है कि इस गुट के चोटी के नेता, इसके संयोजक दिलाश मराक सहित, बंगलादेश में ठहरे हुए हैं। ऐसा बताया गया है कि एचएनएलसी ने बंगलादेश में छुपने के कुछ ठिकाने, आश्रय स्थल तथा प्रशिक्षण शिविर स्थापित किए हैं और इसके कुछ बड़े नेता वहां ठहरे हुए हैं। हलफनामे का पैराग्राफ 4 निम्नवत पठित है:-

"4. यह कि, ऊपर पैराग्राफ 2 और 3 में एएनवीसी तथा एचएनएलसी के यथाउल्लिखित क्रियाकलापों की पृष्ठभूमि में एएनवीसी तथा एचएनएलसी को दिनांक 15-11-2004 से और आगे दो वर्षों की अवधि के लिए विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अंतर्गत 'विधि संगम' के रूप में घोषित करने की अधिसूचना का विस्तार करने तथा इन पर प्रतिबंध जारी रखने के समर्थन में निम्नलिखित कारण हैं;

- क) इस गुट द्वारा हिंसा छोड़ने तथा अपनी मांगे पूरी करने के लिए भारत के संविधान के ढाँचे के अंतर्गत वार्ता करने की अपनी इच्छा व्यक्त करने के बावजूद एएनवीसी द्वारा निधियों का संग्रहण और जबरदस्ती धन ऐंठना, अत्याधुनिक हथियार प्राप्त करना और नए काडरों की भर्ती करना जारी है।
- ख) भारत से मेघालय का पृथक्करण करना एचएनएलसी का खुलेआम घोषित लक्ष्य है।
- ग) इन गुटों द्वारा हथियारों को अपने कब्जे में रखना जारी है।
- घ) अपने संगठन के लिए धन संग्रहण करने हेतु एचएनएलसी द्वारा आम जनता को निरन्तर डराना, धमकाना, उससे जबरदस्ती धन ऐंठना तथा उसे लूटना जारी है।
- ङ) एएनवीसी तथा एचएनएलसी दोनों द्वारा हिंसा करने, जबरदस्ती धन ऐंठने, डराने-धमकाने तथा अपहरण के कार्य करने के लिए और शस्त्र एवं गोला-बारूद प्राप्त करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य विद्रोही समूहों के साथ सम्बन्ध बनाना।
- च) एएनवीसी और एचएनएलसी दोनों द्वारा शरणगाह, प्रशिक्षण तथा शस्त्र एवं गोलाबारूद की चोरी-छुपे खरीद करने के उद्देश्य से बंगलादेश में निरन्तर अपने शिविर बनाना।
- छ) एचएनएलसी प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस तथा गणतंत्र दिवस का बहिष्कार करने का नियमित आह्वान करता है यह राष्ट्रीय दिवसों के खिलाफ विरोध के रूप में उन दिनों लोगों से बंद आयोजित करने के लिए भी कहता है। वर्ष 1998 से गणतंत्र दिवस तथा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर खासी पहाड़ियों, जयन्तियां पहाड़ियों और शिलांग शहर सहित री-भोई जिलों में लगभग पूर्ण बंद आयोजित किया जा रहा है। वर्ष 2004 के दौरान भी इन संगठनों ने स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस दोनों अवसरों पर बंद का आह्वान किया था।

श्री झा के हलफनामे के अनुलग्नक I में एएनवीसी अर्थात् इसके उद्देश्यों, इसके पदाधिकारियों, हिंसा का परिदृश्य अन्य उग्रवादी समूहों के साथ संबंध, वर्ष 1999 से 2003 की अवधि के दौरान इसके विधिविरुद्ध क्रियाकलापों का विवरण दिया गया है। इस हलफनामे के अनुलग्नक 2 में एचएनएलसी के बारे में ऐसा ही विवरण दिया गया है। हलफनामे के अनुलग्नक 3 में वर्ष 2003-2004 के दौरान एएनवीसी द्वारा हिंसा की प्रमुख घटनाओं का विवरण दिया गया है। इस अनुलग्नक में लगभग 25 बड़ी घटनाओं का उल्लेख किया गया है। अनुलग्नक 4 में एचएनएलसी के बारे में ऐसा ही विवरण दिया गया है। इस प्रकार श्री झा का हलफनामा इन कथित विधिविरुद्ध संगमों के विधिविरुद्ध क्रियाकलापों की पूर्ण झलक प्रदान करता है।

मेघालय सरकार की ओर से हलफनामा मेघालय सरकार की राजनीति विभाग, शिलांग की सचिव और आयुक्त श्रीमती आर.वी.सुचियांग द्वारा दायर किया गया था। उनके बयान को सी डब्ल्यू -I के रूप में दर्ज किया गया और इसके साक्ष्य के रूप में उन्होंने अपना हलफनामा प्रस्तुत किया है तथा इसके साथ में उन्होंने अनुलग्नक 1 से 18 तक कुछ अनुलग्नक एवं दस्तावेज भी संलग्न किए हैं। 1 से 18 तक के अनुलग्नकों को सी डब्ल्यू 1/1 से सी डब्ल्यू 1/19 के रूप में दर्शाया गया है। इन प्रदर्शित दस्तावेजों में अखबारों की कतरनों की प्रतियाँ, शिलांग स्टेशन तथा आकाशवाणी द्वारा जारी कारण बताओ नोटिसों की प्रतियाँ हैं और अनुलग्नक 10 में इन संगमों के सदस्यों द्वारा किए गए विभिन्न अपराधों के संबंध में राज्य प्रशासन की जानकारी में लाई गयी घटनाओं या दर्ज विभिन्न मामलों के विवरण दिए गए हैं। वे भारतीय दंड संहिता की धारा 120 (ख), 302, 307, 353, 365, 384, 427 और 511 के अन्तर्गत तथा शस्त्र अधिनियम और विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत किए गए अपराधों से सम्बन्धित है। मुख्यतः ए एन वी सी द्वारा वर्ष 2003 के दौरान किए गए जघन्य अपराधों के 103 मामलों और वर्ष 2004 में किए गए 36 मामलों को अन्य मामलों के विवरणों के

रिकार्डों के साथ रखा गया है। आसूचना रिपोर्ट और स्थानीय समाचार पत्रों की विभिन्न कतरनें रिकार्ड में एक्स.सी.डब्ल्यू. 1/1 से एक्स.सी.डब्ल्यू. 1/19 के रूप में रखी गई हैं जहां यह दर्शाया गया है कि एच एन एल सी ने अनेक अपराधों में लिप्त होने के अलावा तत्कालीन गृह मंत्री श्री रोबर्ट जी. लिंगदोह को धमकी दी थी कि वे सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा न करें और स्वतंत्रता दिवस तथा गणतंत्र दिवस न मनाएं और यहां तक कि जनता को भी धमकी दी थी कि वह स्वतंत्रता दिवस समारोह में सहयोग न करे और उसमें भाग न लें।

मेघालय राज्य ने राज्य के विभिन्न जिलों के 3 उपायुक्तों (सी डब्ल्यू 2, सी डब्ल्यू 3 तथा सी डब्ल्यू 4) तथा 6 पुलिस अधीक्षकों (सी डब्ल्यू 5, 6, 7, 8, 9 तथा 10) से पूछताछ की थी ताकि इस अधिसूचना को जारी करना न्यायोचित ठहराया जा सके। सी डब्ल्यू 2, श्रीमती एल. खरकोंगर, उपायुक्त, जैतियां हिल्स, जिला जोवई ने अपनी मुख्य जिरह में निम्नवत उल्लेख किया है:-

"मैं जैतिया हिल्स जिला, जोवई, मेघालय की उपायुक्त हूँ। मैंने दिनांक 19.5.2003 को इस क्षेत्र के उपायुक्त के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। मैंने श्रीमती आर.वी. सूचिआंग, आई ए एस, आयुक्त एवं सचिव, मेघालय सरकार, राजनीति विभाग द्वारा दायर किए गए शपथपत्रों तथा उनके साथ दायर किए गए दस्तावेजों (प्रदर्शित दस्तावेज, सी डब्ल्यू-1/1 से सी डब्ल्यू 1/19) को भी पढ़ा है। मेरे जिले में हन्नीवट्रैप नेशनल लिब्रेशन कौंसिल (संक्षिप्त में एचएनएलसी) अपने विधिविरुद्ध कार्यकलापों में अचीक नेशनल वालंटियर कौंसिल (संक्षिप्त में 'एएनवीसी') से अधिक सक्रिय हैं। इन गुटों का मुख्य उद्देश्य मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषित करवाना है और भारत संघ का अभिन्न भाग नहीं होना है। मेरे कार्यकाल के दौरान मेरे क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले भूभाग में इन गुटों से संबंधित अनेक घटनाएं हुई हैं। इनमें से कम से कम 9-10 मामले सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालयों को भेजे गए हैं लेकिन कुछ मामलों में आरोप पत्र दायर नहीं किए गए हैं और कुछ मामलों में जांच-पड़ताल पूरी नहीं हुई है। चूंकि इन गुटों के बारे में आम जनता में डर व्याप्त है, इसलिए घटनाओं की संख्या उससे कहीं ज्यादा है जो

1854 GI/08-4

प्राधिकारियों के ध्यान में लाई जाती हैं और अंततः मामले दर्ज किए जाते हैं। मेरे इलाके में इन गुटों के 10 से 15 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। इन गुटों द्वारा किए गए अपराध, जबरन धन ऐंठना, अपहरण, हत्या तथा अन्य संबद्ध अपराधों से संबंधित हैं। इन गुटों के सदस्यों जिमी समर तथा इमलांग सुतंगा को गिरफ्तार किया गया है। उन्हें क्रमशः शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (ख) (क) (1ख) के अंतर्गत थाना खलीहरियत में दर्ज मामला सं. 92 (1) (03) के तहत तथा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10 तथा 13 के साथ पठित भा.दं.सं. की धारा 384/511/120(ख)/121 के अंतर्गत थाना जोवई में दर्ज मामला सं. 14 (1) 2005 के तहत तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के साथ पठित भा.दं.सं. की धारा 395/397 के अंतर्गत थाना खलीहरियत में दर्ज मामला सं. 7 (1) (05) के तहत गिरफ्तार किया गया है। जनवरी, 2005 में मेरे क्षेत्राधिकार में एक बैंक डकैती हुई जो मेघालय कोऑपरेटिव अपैक्स बैंक, खलीहरियत शाखा में हुई। इमलांग सुतंगा, जो गिरोह का सदस्य था, को डकैती डालने के लिए गिरफ्तार किया गया और वह एच एन एल सी के विधिविरुद्ध क्रियाकलापों से जुड़ा हुआ है। समय-समय पर गिरफ्तार किए गए इन गुटों ने सदस्यों से शस्त्र तथा गोलाबारूद बरामद किए गए हैं। जैतिया हिल्स जिले में कोयले की खदानें हैं और इस क्षेत्र में समृद्ध व्यापारी वर्ग इस क्षेत्र में रहता है। इन गुटों का मुख्य निशाना यह समृद्ध व्यापारी वर्ग है जिनसे वे धन लूटने की कोशिश करते हैं। इन संगठनों के अन्य प्रतिबंधित गुटों विशेष रूप से नेशनल सोशलिस्टिक कौंसिल ऑफ नागालिम के साथ संबंध है। इन विधिविरुद्ध गुटों के कार्यकलाप, विशेष रूप से अन्य प्रतिबंधित गुटों के साथ साजिशें भारत की प्रभुसत्ता, एकता और आंतरिक तथा बाह्य सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं।"

अन्य जिलों के उपायुक्तों ने भी इसी प्रकार के बयान दिए हैं और यहां तक कि अपने क्षेत्राधिकार के भीतर ए एन वी सी तथा एच एन एल सी द्वारा की गई घटनाओं, अपराधों तथा विधिविरुद्ध कार्यकलापों का भी हवाला दिया है। उन्होंने अपने बयानों के समर्थन में विशेष रूप से एक्स सी डब्ल्यू 1/1 से सी डब्ल्यू 1/19 तक के दस्तावेजों का भी हवाला दिया है। इसी प्रकार श्री ए.एस. रिंजाह, पुलिस अधीक्षक, ईस्ट खासी हिल्स जिला, शिलांग से सी डब्ल्यू -5 के रूप में पूछताछ की गई और उनकी मुख्य जिरह का पाठ निम्नवत है :-

"मैं इस समय ईस्ट खासी हिल्स जिला, शिलांग में पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। इस जिल में मेरी तैनाती दिनांक 27 अक्टूबर, 2003 को हुई थी। मैंने सुश्री आर0वी0 सुचिआंग, आई ए एस, आयुक्त एवं सचिव, मेघालय सरकार, राजनीति विभाग द्वारा दायर किए गए शपथ पत्र तथा उनके साथ दायर किए गए दस्तावेजों (प्रदर्शित दस्तावेज सी डब्ल्यू 1/1 से सी डब्ल्यू 1/19) को पढ़ा है। वे रिकॉर्ड की सही प्रतियाँ हैं। इन अनुलग्नकों में विधिविरुद्ध संगमों, अर्थात् अचीक नेशनल वालंटियर कौंसिल (एएनवीसी) तथा हन्नीवट्रेप नेशनल लिब्रेशन कौंसिल (एचएनएलसी) द्वारा मेरे क्षेत्राधिकार में किए गए विधिविरुद्ध क्रियाकलापों/अपराधों का उल्लेख किया गया है।

उपर्युक्त दोनों विधिविरुद्ध संगमों में से हन्नीवट्रेप नेशनल लिब्रेशन कौंसिल अधिक सक्रिय है। मेघालय राज्य की राजधानी शिलांग मेरे क्षेत्राधिकार का भाग है। इन दोनों विधिविरुद्ध संगमों का मुख्य उद्देश्य पृथक "गारो लैंड" तथा "खासी हिल्स" नामक ऐसे राज्यों का गठन करना है जो भारत संघ का हिस्सा नहीं होंगे।

वर्ष 2003 के दौरान, मेरे क्षेत्राधिकार में विभिन्न पुलिस थानों में 27 मामले दर्ज किए गए थे जबकि वर्ष 2004 में 3 मामले दर्ज किए गए।

गंभीर परिणामों वाली एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना जिसका मैं अधिकरण के समक्ष उल्लेख करना चाहता हूँ निम्नवत है :-

"दिनांक 16 सितम्बर, 2004 को पुलिस ने मावलाई मॉदतबाकी शिलांग से एचएनएलसी के एक काडर शंबोर वाजरी उर्फ बह दुह शी को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से सजीव गोला बारूद के 8 राउंड से भरी हुई 9 एम एम की एक पिस्तौल जब्त की गई। उसके बताने पर मावलाई उमजयपुर, शिलांग में एक घर से एक ए के असाल्ट राईफल, पांच मैगजीन तथा सजीव ए के गोलाबारूद के 107 राउंड बरामद किए गए। इसका हवाला विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित सशस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1-क)/27 के अंतर्गत थाना मावलाई में दर्ज मामला सं0 44(9)04 में दिया गया है।

मैं आगे यह भी उल्लेख करता हूँ कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था वह हन्नीवट्रेप नेशनल लिब्रेशन कौंसिल के उच्चतर काडर का है और उसे गुट के सबसे वरिष्ठतम व्यक्तियों द्वारा भेजा गया था जिनका मुख्यालय बंगलादेश में है और उसे शिलांग

में दो लक्ष्यों के साथ भेजा गया था। एक लक्ष्य था-पृथक राज्य के उद्देश्य को प्राप्त करना तथा दूसरा उद्देश्य था एचएनएलसी के उन सदस्यों को खत्म करना जिन्होंने विगत में उनका विश्वास तोड़ा है। वे इन दोनों लक्ष्यों को सशस्त्र संघर्ष के जरिए प्राप्त करना चाहते थे। उनके मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य धन एकत्र करना भी है जिसका संग्रह वे लोगों के मन में भय पैदा करके तथा यह सुनिश्चित करते हुए कि वे जैसे और जब कभी भी मांग होगी तब इसकी आपूर्ति कर देंगे, लोगों से धन छेड़ कर करते हैं। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ की कई घटनाएं हुई हैं किन्तु मेरे कार्यकाल के दौरान किसी भी पुलिस अधिकारी की मौत नहीं हुई। इससे पूर्व, पुलिस अधिकारियों की मौत की कुछ घटनाएं हुई थीं। विभिन्न मौकों पर, इन दोनों विधिविरुद्ध संगमों के गिरफ्तार सदस्यों से भारी मात्रा में हथियार एवं गोला-बारूद बरामद किए गए हैं। इनसे बरामद सामग्री में ए के -47 राइफल्स, 9 एम.एम. पिस्तौल तथा भारी मात्रा में गोलाबारूद शामिल है। ऐसी कुछ घटनाएं निम्न प्रकार हैं- जिनमें इन दोनों संगमों के सदस्यों तथा वास्तव में मेरे क्षेत्राधिकार के अधीन आने वाले विभिन्न पुलिस थानों पर हमला किया गया :

"12/8/2003 : संदिग्ध एच.एन.सी.एल उग्रवादियों ने मावलाई पुलिस थाना परिसर पर एक हथगोला फेंका। इस घटना में कांस्टेबल, 147 फील्डस्टोन संगमा को छाती पर गंभीर चोटें आईं। (भा.द.स. की धारा 353 और विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/3 के साथ पठित आई ई एस अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत मावलाई पुलिस थाने में दर्ज मामला सं. 38(8)03)

14/08/03: संदिग्ध एचएनसीएल उग्रवादियों ने लुंबडिएनगजरी पुलिस थाने पर एक हथगोले से हमला करने का प्रयास किया किन्तु ग्रेनेड पुलिस थाने के निकट सड़क पर ही फट गया। (भारतीय दंड संहिता की धारा 307/34 और विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आईईएस अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत लुंबडिएनगजरी पुलिस थाने में दर्ज मामला सं0 125(8) 03)

16/08/03: संदिग्ध एचएनएलसी उग्रवादियों ने पीटीएस, मवलाई मारोह, शिलांग पर एक हथगोला फेंका। ग्रेनेड कार्यालय इमारत के पास ही फट गया जिससे खिड़की के शीशों को क्षति पहुंची। (भारतीय दंड संहिता की धारा 307/34 और विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आईईएस अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत सदर पुलिस थाने में दर्ज मामला सं0 233 (8) 03)



इन संगमों के सदस्यों द्वारा अंजाम दी गई कुछ घटनाओं अथवा अपराधों की तो भय के मारे रिपोर्ट तक नहीं की गई है। तथापि, मेरे जिले में, मैं आतंकवादी गतिविधियों को कम करने में सफल रहा हूँ। इन संगठनों का मुख्य निशाना व्यावसायिक वर्ग है क्योंकि ये संगठन उनसे आसानी से धन ऐंठ सकते हैं। इन विधिविरुद्ध संगमों के अन्य प्रतिबंधित विधिविरुद्ध संगमों जैसे कि नेशनल सोशलिस्ट कौंसिल ऑफ नागालिम (इसाक मुइवाह) तथा एनएलएफटी से सीधे संबंध है।

एचएनएलसी को उल्लिखित विधिविरुद्ध संगमों से प्रशिक्षण एवं सहयोग प्राप्त होता है। इन विधिविरुद्ध संगमों के बीच गहरा संबंध है तथा उनकी मंशा इस राज्य में शांतिपूर्ण जीवन को भंग करने तथा राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा करने की है।

इन विधिविरुद्ध संगमों की गतिविधियाँ, विशेषकर अन्य प्रतिबंधित संगमों के साथ मिलकर किए जाने वाले षड़यंत्र भारत की प्रभुसत्ता, अखंडता, आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है।

अन्य पुलिस अधिकारियों ने भी जिनसे सीडब्ल्यू-1 से सी डब्ल्यू-10 के रूप में पूछताछ की गई थी इसी तरह के बयान दिए हैं तथा उन्होंने अपने क्षेत्राधिकार के अधीन एचएनएलसी तथा एएनवीसी द्वारा किए गए कुछ जघन्य अपराधों एवं विधिविरुद्ध गतिविधियों का हवाला दिया है। उन्होंने अपने बयानों के समर्थन में एक्स सी डब्ल्यू-1 से सी डब्ल्यू-10 तक का विशेष रूप से उल्लेख किया तथा उन पर विश्वास किया है।

जैसा कि पहले देखा गया है कि इन सभी गवाहों को अपने रिकार्डों के साथ प्रतिपरीक्षण हेतु उपस्थिति कराया गया लेकिन चूंकि उनका प्रतिपरीक्षण करने के लिए कोई उपस्थित नहीं हुआ अतः उन्हें छोड़ दिया गया। सी डब्ल्यू-11 के रूप में परीक्षित श्री आर. आर. झा को भी प्रतिपरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया और अनुलग्नकों के साथ उनके हलफनामे को एक्स0 सी0 डब्ल्यू0 11/क के रूप में प्रदर्शित किया गया। केन्द्र सरकार के साथ-साथ मेघालय राज्य की सरकार की ओर से प्रस्तुत विस्तृत साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि यह संगम विधिविरुद्ध क्रियाकलापों में संलिप्त हैं और जघन्य अपराधों में शामिल रहने के अलावा वे आम लोगों के मन में भय पैदा करते हैं जिससे कि राज्य का प्रशासन स्पष्ट रूप से

1554 62/05-5

बाधित होता है। एच एन एल सी ने मेघालय को भारत से अलग कर एक स्वतंत्र राज्य के गठन के अपने उद्देश्यों को दृढ़तापूर्वक प्रदर्शित किया है। ए वी एन सी जबरन वसूली, हत्या, अपहरण तथा राज्य प्रशासन और सुरक्षा बलों के विरुद्ध हिंसात्मक कार्रवाई करने जैसे अपराध सहित विभिन्न विधिविरुद्ध क्रियाकलापों में संलिप्त है।

इस अधिनियम की धारा 2 (ण) के तहत विधिविरुद्ध क्रियाकलापों की परिभाषा को 'अथवा' शब्द को जोड़कर उसमें (i), (ii) तथा (iii) शामिल करते हुए संशोधित किया गया है। इस परिभाषा खंड के संशोधन ने 'विधिविरुद्ध क्रियाकलाप' की अभिव्यक्ति के विषय-क्षेत्र को महत्वपूर्ण ढंग से परिवर्तित कर दिया है। पूर्व संशोधित परिभाषा खंड में (i) तथा (ii) दोनों घटकों को संतुष्ट किया जाना चाहिए जबकि संशोधित खंड के तहत धारा 2 की उप धारा (ण) के तहत उल्लिखित तीनों खंडों में से किसी एक के भी होने के अवस्था में इसे 'विधिविरुद्ध क्रियाकलाप' माना जाएगा। "कोई भी व्यक्ति अथवा संगम", जो कि भारत के विरुद्ध अलगाव पैदा करता है या अलगाव पैदा करने के कार्य के प्रति उन्मुख है", वह "व्यक्ति" अथवा "संगम" विधिविरुद्ध क्रियाकलापों में संलिप्त समझा जाएगा। "अलगाव" की व्याख्या में विश्वासहीनता तथा शत्रुता के सभी भावों को सम्मिलित किया गया है। यह एक प्रकार का अलगाव है और लोग सरकार से अलग होने लगते हैं। सरल भाषा में, यह सरकार को गैर कानूनी साधनों से चुनौती देने का एक तरीका है। इस अभिव्यक्ति को व्यापक अर्थ प्रदान करते हुए एक बंगाली पाक्षिक समाचार पत्र "सप्ताह" तथा विनय कुमार चट्टोपाध्याय ए आई आर 1950 कोलकाता 445 के मामले में कोलकाता उच्च न्यायालय की एक पीठ ने निम्नलिखित व्याख्या की है:-

" 'अलगाव' शब्द राजनीतिक विराग अथवा असंतोष तथा यह कहा जाए कि मौजूदा सरकार के प्रति विश्वासहीनता की भावना को दर्शाता है जिससे की आज्ञा का पालन न कर प्रतिरोध करने और सरकार को पलटने की ओर उन्मुख हुआ जाता है"

" विधिविरुद्ध संगम" की धारा 2(त) ऐसे संगम के रूप में परिभाषित करती है -

"जिनके अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विधिविरुद्ध क्रियाकलाप हों, अथवा जो लोगों को किसी प्रकार के विधिविरुद्ध क्रियाकलाप करने के लिए सहायता अथवा प्रेरित करता है, अथवा जिसके सदस्य ऐसे क्रियाकलापों में संलिप्त हैं।" यह विधायन परिभाषा वाली इस उप-धारा को व्यापक अर्थ तथा व्याख्या प्रदान करने के प्रति उन्मुख है और यही वह विशेष कारण है कि इस खंड में 'प्रेरित' 'सहायता' जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। यहां तक कि ऐसा

कोई भी संगम जो अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऐसे क्रियाकलाप करते हैं जो भारतीय दंड संहिता की धारा 153 क अथवा 153 ख के अंतर्गत दंडनीय है अथवा जिसके स्वरूप ऐसे क्रियाकलाप में संलिप्त हैं, "विधिविरुद्ध संगम" होंगे। अधिकरण के लिए ऐसा कोई अवसर नहीं है कि इसे वह एक सीमित अर्थ/व्याख्या प्रदान करे। जैसे भी मामले हों, इन दोनों संगमों - एएनवीसी तथा एचएनएलसी के उपर्युक्त पाए गए क्रियाकलाप, धन की जबरन वसूली, व्यपहरण, सुरक्षा बलों पर हमले तथा उनकी हत्या जैसे उनके विधिविरुद्ध क्रियाकलाप लोगों के मन में भय उत्पन्न करते हैं जो कि विधिविरुद्ध तथा गैर कानूनी साधनों के द्वारा इन संगमों की ओर से प्रशासन के लिए अड़चनें पैदा करने के प्रयासों का स्पष्ट सूचक है। वस्तुतः ये संगम अभी भी हथियारों के प्रापण, भारत संघ की सीमाओं का अतिक्रमण, भारतीय क्षेत्र की क्षेत्रीय सीमा के अन्दर तथा बाहर प्रतिबंधित संगठनों तथा विधिविरुद्ध संगमों के साथ अपने संबंधों को कायम रखे हुए हैं।

#### **भारत संघ तथा अन्य बनाम सुकुमार सेन गुप्ता और अन्य प्रकरण, 1990**

**(अनुपूरक) के मामले में सुप्रीम कोर्ट केसेज, 545** में न्यायालय द्वारा प्रभुसत्ता को अधिकारों की गुणवत्ता और अधिकारों के रूप में परिभाषित किया गया था जो प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। आधुनिक विकसित समाज की जटिलताओं को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को सौहार्द्र और शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए जाने की आवश्यकता है तथा प्रभुसत्ता की अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता को घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए संशोधित किया जाना है। इस अधिकार के नाते अपने समाज के सदस्यों की सुरक्षा का दायित्व राज्य का है जिसे उच्च स्थान पर रखा गया है। अतः मौजूदा कानून के अनियत सिद्धांतों को उस दिशा में विधिविरुद्ध तरीके से एकत्रित करने और विधिविरुद्ध कार्यकलापों की व्याख्या करने की आवश्यकता है। यदि इन विधिविरुद्ध संगमों के सदस्य सड़क पर आम आदमी को भयाक्रांत कर रहे हैं तथा उपर्युक्त उद्देश्यों से सामान्य प्रशासन के लिए कानून

और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करते हैं तो वह न केवल इरादतन होगा अपितु वह भारत की प्रभुसत्ता और क्षेत्रीय अखण्डता को बाधित करने वाला होगा।

प्रभुसत्ता की अवधारणा की महत्ता को स्पष्ट करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने **सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड तथा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य (1990) 1 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के सेज 109** में माना कि "यह सम्प्रभुता की शक्ति का प्रयोग है जो राज्य को अपने कार्य करने के लिए संविधान की सीमाओं के अध्यधीन किसी भी कानून को अधिनियमित करने का पर्याप्त प्राधिकार देती है। भारतीय राज्य में केन्द्र और राज्यों के बीच सम्प्रभु शक्ति विद्यमान है। प्रत्येक सम्प्रभु राज्य में सभी कार्यों को करने के लिए सम्प्रभुता पूर्णरूप से अन्तर्निहित है जो लोगों के स्वास्थ्य, शान्ति, नैतिक आचरण, शिक्षा और सुव्यवस्था को प्रौन्नत करती है। तथापि सम्प्रभुता की यह शक्ति संवैधानिक सीमाओं के अध्यधीन है।"

विधि के उपर्युक्त वाणंजित सिद्धांत इंगित करते हैं कि "सम्प्रभुता" की अभिव्यक्ति को एक ऐसा अर्थ देना है जो आम सम्भाषण (बोलचाल की रीति) में समझा जाता हो और जिसकी व्यापक आयामों में एक निश्चित अभिव्यक्ति हो। सम्प्रभुता के अधिकार का उद्देश्य अंततः राज्य के लोगों के कल्याण के लिए है। किसी संगठन अथवा व्यक्तियों के समूह से प्राप्त धमकी और विधिविरुद्ध रूकावटों से बाधित हुए बिना इस प्रकार अपना कार्य करना कि लोकतांत्रिक प्रणाली की मूल अवधारणाओं का उल्लंघन न हो।

यह दशनि के लिए रिकार्ड में निश्चित अभिलेखीय, मौखिक और विशिष्टिकृत साक्ष्य हैं कि ये विधिविरुद्ध संगम अधिनियम के उपबंधों की भावना के दायरे में विधिविरुद्ध क्रियाकलापों में संलिप्त हैं। इन विधिविरुद्ध संगमों के विधिविरुद्ध क्रियाकलाप केवल निमित्त ही नहीं है अपितु उनकी गतिविधियां राज्य, भारत संघ की सम्प्रभुता को खतरा पहुंचाने और अपनी मांगों के संबंध में एक स्वतंत्र राज्य बनाते हुए मेघालय को भारत संघ से अलग करने

के एचएनएलसी के मुख्य उद्देश्य के लिए हैं। उनकी पूर्वोक्त विधिविरुद्ध गतिविधियों के प्रत्यक्ष परिणामों से भारत की क्षेत्रीय अखण्डता और सम्प्रभुता को खतरा पैदा होगा और वह खण्डित होगी। राज्य और केन्द्र सरकार ने इन संगमों को 'विधिविरुद्ध' घोषित करने के पर्याप्त कारण विद्यमान होने के संबंध में प्राधिकरण के समक्ष किए गए अपने अनुरोध को प्रमाणित करने के अपने दायित्व का पूरी तरह से निर्वाह किया है।

मेरे उपर्युक्त विस्तृत विचार-विमर्श को ध्यान में रखते हुए मेरा दृढ़ विचार है कि एएनवीसी और एचएनएलसी को 'विधिविरुद्ध संगम' घोषित करने का पर्याप्त कारण मौजूद है। अतः मैं केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 3(1) के अंतर्गत जारी दिनांक 16 नवम्बर, 2004 की अधिसूचना की सम्पुष्टि में धारा 4, उप धारा (3) के अनुरूप यह आदेश पारित करता हूँ।

ह0/-

( स्वतंत्र कुमार )

पीठासीन अधिकारी

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण

मई 12, 2005

[फा. सं. 11011/47/2004-एन.ई. III]

राजीव अग्रवाल, संयुक्त सचिव

1554 GI/05-6

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th May, 2005

**S.O. 680(E).**—In terms of Section 4(4) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the order of the Tribunal presided over by Hon'ble Justice Swatanter Kumar, Judge, Delhi High Court, to whom a reference was made under Section 4(1) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the associations, namely the Achik National Volunteer Council (ANVC) and Hynniewtre National Liberation Council (HNLC) Organisations of Meghalaya as unlawful is published for general information :

**BEFORE THE UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION)  
TRIBUNAL CONSISTING OF HON'BLE MR. JUSTICE  
SWATANTER KUMAR**

12-05-2005

In the matter of : Notification No. S.O. 1266(E) dated 16-11-2004 Government of India, Ministry of Home Affairs, Part II—Section 3, Sub-section (ii) declaring Achik National Volunteer Council and the Hynniewtre National Liberation Council of Meghalaya, as unlawful associations.

**ORDER**

Ministry of Home Affairs, Government of India, on 16th of November, 2004 issued the following notification :—

**“MINISTRY OF HOME AFFAIRS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th November, 2004

**S.O. 1266(E).**—Whereas the Achik National Volunteer Council (hereinafter referred to as the ‘ANVC’) of Meghalaya have continued collection of funds and extortion, acquisition of sophisticated weapons and recruitment of new cadres despite having agreed to abjure violence and having expressed their willingness to hold talks within the framework of the Constitution of India for fulfilling their demands :—

And whereas, the Hynniewtre National Liberation Council (hereinafter referred to as HNLC) of Meghalaya have been :—

- (i) openly declared as their objective the secession of the State of Meghalaya from Indian Union ;
- (ii) employing and engaging in armed means to achieve their objective ;
- (iii) indulging in acts of intimidation, extortion and looting of civilian population for collection of funds for their organization ;

And whereas, both ANVC and HNLC have been,—

- (i) maintaining links with other insurgent groups of the North Eastern Region for procuring arms and ammunition and for carrying out acts of violence, extortion, intimidation and looting ;
- (ii) maintaining camps in some neighbouring countries for the purpose of sanctuary, training and clandestine procurement of arms and ammunition ;

And whereas, the Central Government is of the opinion that for the reasons aforesaid, the ANVC and the HNLC and other bodies set up by them, are unlawful associations ;

And whereas, the Central Government is further of the opinion that the aforesaid activities of the ANVC and the HNLC are detrimental to the sovereignty and integrity of India, and if these are not immediately curbed and controlled, the said ANVC and HNLC would regroup and rearm themselves, expand their cadres, procure sophisticated weapons, cause heavy loss of lives of civilians and Security Forces, and accelerate their activities aimed at secession of Meghalaya from India ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the Achik National Volunteer Council (ANVC) and the Hynniewtre National Council (HNLC) alongwith all their factions, wings and front organisations to be as unlawful associations ;

The Central Government is of further opinion that it is necessary to declare the ANVC and the HNLC alongwith all their factions, wings and front organisations to be as unlawful with immediate effect and accordingly,

in exercise of the powers conferred by the proviso to Sub-section (3) of Section 3, the Central Government hereby directs that this notification shall, subject to any order that may be made under Section 4 of the said Act, have effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 11011/47/2004-NE. III]

H. S. BRAHMA, Jt. Secy.”

By Notification dated 15th December, 2004 the Central Government constituted “Unlawful Activities Prevention Tribunal” consisting of the undersigned, under Section 5(1) of the Unlawful Activities Prevention Act, 1967 (hereinafter referred to as ‘the Act’) and referred the above notification to the Tribunal for the purposes of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the above-mentioned associations “unlawful”. Before I proceed to discuss the allegations, the evidence and legal aspects in relation to the aforesaid notification dated 16th November, 2004, certain historical background, as it appears from the record, can be usefully referred at the very outset of this report.

The Achik National Volunteer Council (hereinafter referred to as ‘ANVC’) and Hynniewtre National Liberation Council (hereinafter referred to as the ‘HNLC’) are stated to have declared as ‘unlawful association’ under the relevant provisions of the Act vide notification dated 16th November, 2004. Previously, a reference under Sub-section (1) of Section 4 of the Act was made to the Tribunal constituted by the Central Government, which vide its order dated 6th June, 2003 had confirmed the declaration made by the Central Government vide Notification dated 16th November, 2002. It is the case of the Central and concerned State Governments that ANVC was formed in December, 1995 with the aim of, among other things, liberation of Garo Hills to achieve a new State of ‘Achik Land’ to prevent the influx of non-tribals and exploitation of Garos. It is averred that ANVC had agreed to abjure violence and have expressed their willingness to hold talks within the framework of the Constitution of India for fulfilling their demands, but the cadres of ANVC continued to indulge in extortion from business community, contractors on practice and also from common people. They are also continuing with the recruitment of new cadres in their organisations.

HNLC is stated to have been formed in 1992 with the aim of liberation of Hynniewtre people from authoritarian rule of Indian Government, protect the *khasis* and other Meghalayan tribes from alleged exploitation, retain indigenous culture and to eradicate the social evils. The secession of State of Meghalaya from India is their basic object. HNLC have not expressed their willingness to abjure from violence and hold talks within the framework of the Constitution for fulfillment of their demands. The organisation have links with other insurgent groups of north-eastern region. Amongst other unlawful activities, they are also indulging in extortion from businessmen and the people in general.

ANVC is active in Garo Hills districts particularly East Garo Hills. Its cadres have been receiving training in Bangladesh in the National Socialist Council of Nagaland (NSCN) camps. Top leaders of this outfit are reportedly staying in Bangladesh, while HNLC is primarily operating in Shillong City and some areas of East Khasi Hills, West Khasi Hills and Ri-Bhoi districts. HNLC has also established some hideouts, shelters and training camps in Bangladesh. Some of its top ranking members, including the Chairman/Commander-in-Chief are staying in Bangladesh. The total strength of the cadre of ANVC is 250 and the total weaponry of the outfit is estimated at 70. Major portion of its cadre strength and weaponry is still underground and top leaders are hiding in Bangladesh. The capacity of this organisation to strike has not yet been neutralised. It is the specific case that ANVC is maintaining close links with NSCN, which is helping it in procuring arms and ammunition, training of cadres and also in joint operations. The outfit is also maintaining close links with United Liberation Front of Assam (ULFA) and National Democratic Front of Bodoland (NDFB). During the year 2001-2002, the violence showed steady and significant increase with number of killings and acts of extortion and violent attack on personnel of security forces. An agreement of suspension of operation was signed on 23rd July, 2004 between the Government of India, Government of Meghalaya and ANVC. Though, after signing of ceasefire agreement, there have been no killings, but other activities have not been completely stopped, and if the ban is lifted and laxity is there in counter-insurgency operation, there is every likelihood of ANVC getting a new lease of life in a more aggravated form.

Violence of HNLC had declined in 2003 due to counter-insurgency operations and there was surrender of 74 undergrounds, which dissuaded the violence activities, particularly in Shillong to a great extent. A number of arrests were made and 12 ANVC militants in armed encounter were shot dead. Keeping in view the unlawful activities of these unlawful associations, the Ministry of Home Affairs had sought the views of Government of Meghalaya, Ministry of Defence, Army Headquarters, Intelligence Bureau, Research and Analysis Wing (RAW), Central Reserve Police and the Border Reserve Force. Army Headquarters and Ministry of Defence while agreeing with the views of each other recommended extension of ban for a period of one year from 15th November, 2004. However, according to Intelligence Bureau the outfits continued to believe in path of violence and therefore the ban should not be lifted and the other authorities also recommended the continuation of the ban in view of the fact that during the past one year, these outfits had indulged in a number of insurgent activities in Meghalaya, indulged in extortion from business community, contractors and even common people and both groups have kept up their insurgency profiles and continue to train their cadres in use of small arms and guerilla warfares in camps inside Meghalaya as well as across the border in Bangladesh.

After issuance of the notifications dated 16th November, 2004 and 15th December, 2004 respectively, the first hearing of the Tribunal was held at New Delhi on 6th January, 2005, on which date it was directed that notices be issued to the said Associations, by publication in the newspapers as well in terms of the directions contained in the order dated 18th February, 2005. Affidavit of Sh. R.R. Jha, Director to Government of India, Ministry of Home Affairs, New Delhi was filed stating that the notices were published in four local newspapers namely, The Telegraph Kolkata dated 13th January, 2005, The Shillong Times dated 12th January, 2005, The U Mawphor dated 12th January, 2005 and Salentini Janera dated 13th January, 2005. Copies of the cuttings of the relevant newspapers have been placed on record along with the affidavit. In the said affidavit it has also been stated that according to the Government of Meghalaya, notices had been telecasted in programme of 'City Scan' of the Doordarshan Kendra, Shillong on 12th January, 2005 and had been broadcasted through the Shillong Station of All India Radio on 12th January, 2005 and in addition thereto notices were also affixed at public places and notice boards of the Deputy Commissioners of all the seven districts of the State of Meghalaya. In terms of the said affidavit, it is stated that the notices could not directly be served on these associations because their exact locations are not fixed and are not known to the Administration. Being satisfied with the mode of service, The Tribunal had directed that the matter be heard even in absence of these associations, as despite such wide publicity of the notice through publication in the newspapers and electronic media, none had appeared on behalf of these associations. In terms as contemplated under Sections 5(5) and 5(6) of the Act, the Tribunal while conducting an enquiry under the provisions of the Act, shall have powers to regulate its own procedure in all matters arising out of the discharge of its functions and also have the same powers as are vested in a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908. The record before the Tribunal clearly exhibits that the unlawful associations have been sufficiently served by the above means of service and in the interest of justice, sufficient opportunities have been granted to them to appear before the Tribunal. Having failed to put in appearance despite due notice, the proceedings were ordered to be continued in absence of the concerned.

On 28th February, 2005, affidavit of Sh. R.R. Jha was tendered in evidence. He was offered for cross-examination. As nobody was present to cross-examine him, the affidavit was taken on record. As per request of the Counsel appearing for the State of Meghalaya, they were granted 15 days time to file affidavit on behalf of the State of Meghalaya. Then the case was fixed for 30th and 31st March, 2005, for recording of evidence at Shillong as a number of witnesses from that area were to be examined in support of the notification. On 30th March, 2005 the Tribunal made the following order :—

“The proceedings of the Tribunal commenced at 10.30 a.m., as scheduled.

In terms of the order of the Tribunal, notices were published in the newspapers as well as affixed at the appropriate places. The proof of service in terms of the earlier order has also been filed in the Court. Despite due notice, nobody is present on behalf of the two alleged unlawful organisations, i.e. ANVC and HNLC. None was present on their behalf even on the previous date of hearing, i.e., 18-2-2005 at New Delhi. As none is present on their behalf even today, the Tribunal shall proceed with the matter in accordance with law and in their absence.

Learned counsel appearing for the State of Meghalaya has filed the list of witnesses to be examined on behalf of the State. Out of 15 witnesses mentioned in the list, the State proposes to examine only 10 witnesses. He also submits that Commissioner-cum-Secretary to the Govt. of Meghalaya, Political Department has already filed an affidavit by way of evidence. She is present in Court and prays that her statement be also recorded. Let the statement of Commissioner-cum-Secretary and the other witnesses be recorded.”

Accordingly, statements of ten witnesses, being CW-1 to CW-10 were recorded. All these witnesses were offered for cross-examination but as there was nobody present on behalf of the alleged unlawful associations even at Shillong, the witnesses were discharged. Learned Counsel appearing for the State of Meghalaya closed his evidence on behalf of the State. However, Counsel appearing for the Union of India had prayed that statement of Mr. R.R. Jha may also be recorded, though, his affidavit had already been tendered in evidence. It was further requested that the statement of Mr. Jha be recorded at New Delhi as he could not be present at Shillong due to unavoidable circumstances. Request of the counsel was allowed and the matter was fixed for examination of Mr. R.R. Jha and for other proceeding on 11th April, 2005 at New Delhi. On 11th April, 2005 statement of Mr. R.R. Jha, had been recorded. The matter was taken up for hearing on 15th April, 2005, 21st April, 2005, and lastly on 3rd May, 2005 when arguments were concluded and the matter was reserved for orders.

Affidavit of Mr. R.R. Jha, in support of the notification was filed along with five annexures, It is stated in the affidavit that ANVC had been indulging in continued collection of funds and extortion from business community, contractors and also from common people, acquisition of sophisticated weapons and recruitment of new cadres by ANVC despite the fact that the outfit having agreed to abjure violence and having expressed their willingness to hold talks within the framework of the Constitution of India for fulfilling their demands. It is further stated in the affidavit that the objective of HNLC continues to be liberation of Hynniewtrep people, secession of the State of Meghalaya from India and HNLC have



not shown their willingness to abjure violence and hold talks. There is a specific and definite reference that ANVC cadres have been receiving training in Bangladesh in NSCN camps, and top leaders of the outfit, including its convener, Dilash Marak, are reportedly staying in Bangladesh. HNLC is stated to have established some hideouts, shelters and training camps in Bangladesh and some of its top leaders are staying there. Paragraph 4 of the affidavit reads as under :—

“4 That, in the background of the activities of the ANVC and the HNLC as given in paras 2 and 3 above, following were the reasons in support of the proposal for continuance of the ban and extension of the notification declaring the ANVC and HNLC as ‘unlawful associations’ under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for a further period of two years beyond 15-11-2004;

(a) Continued collection of funds and extortion, acquisition of sophisticated weapons and recruitment of new cadres by ANVC despite the outfit having agreed to abjure violence and having expressed their willingness to hold talks within the framework of the Constitution of India for fulfilling their demands.

(b) Openly declared objective of HNLC of secession of Meghalaya from India.

(c) Continued possession of weapons by these outfits.

(d) Continued intimidation, extortion and looting of civilian population by HNLC for collection of funds for their organization.

(e) Maintaining links with other insurgent groups of the North Eastern Region by both ANVC and HNLC for procurement of arms and ammunition and for carrying out acts of violence, extortion, intimidation and kidnappings.

(f) Continued maintenance of camps by both ANVC and HNLC in Bangladesh for the purpose of sanctuary, training and clandestine procurement of arms and ammunitions.

(g) The HNLC is regularly giving calls for boycott of the Republic Day and Independence Day every year. It has also been asking the people to observe *bandh* on these days to mark protest against the national days. Since 1998, near total *bandhs* are being observed in the Khasi Hills, Jaintia Hills and Ri-Bhoi Districts, including Shillong City, on the occasions of Republic Day and Independence Day. During the year 2004 also, the outfit on the occasion of both Republic Day and Independence Day called *bandhs*.”

Annexure 1 to the affidavit of Mr. Jha gives details in relation to ANVC i.e. of their aims and objectives, office bearers, violence profiles, links with other extremist groups, their unlawful activities during the period 1999 to 2003. Annexure 2 to this affidavit provides similar details about HNLC. Annexure 3 to the affidavit gives details of major incidents of violence by ANVC during 2003-2004. As many as 25 major incidents have been referred in this annexure. Similar information is provided in Annexure 4 about HNLC. The affidavit of Mr. Jha thus, provides complete insight to the unlawful activities of these alleged unlawful associations.

Affidavit on behalf of the State of Meghalaya was filed by Smt. R.V. Suchiang, Commissioner and Secretary to the Government of Meghalaya, Political Department, Shillong. Her statement was recorded as CW 1 and she tendered her affidavit in evidence and along with this she had annexed some documents and Annexures 1 to 18. Annexures 1 to 18 were exhibited as CW 1/1 to CW 1/19. These exhibited documents are the copies of the newspaper clipping, copies of the show-cause notices issued through Shillong Station and All India Radio, and Annexure 10 gives details of various cases which were registered or the incidents brought to the notice of the State administration in relation to various criminal offences committed by the members of these associations. They related to offences under Sections 120B, 302, 307, 353, 365, 384, 427 and 511 of the Indian Penal Code and provisions of the Arms Act and Section 13 of the U.A. (P) Act. As many as 103 cases of heinous crimes in relation to the year 2003, and 36 in relation to the year 2004 were placed on record amongst details of many other cases which were mainly attributable to ANVC. Copies of the Intelligence Report and various cuttings of the local paper were placed on record as Ex. CW 1/1 to Ex. CW 1/19, where it is shown that HNLC besides being involved in number of crimes also threatened the Home Minister Mr. Robert G. Lyngdoh not to visit the border areas and not to celebrate the Independence Day and Republic Day and even threatened the public at large not to co-operate with Independence Day celebrations and boycott the same.

State of Meghalaya had examined 3 Deputy Commissioners (CW 2, CW 3 and CW 4) and 6 Superintendent of Police (CW 5, 6, 7, 8, 9 and 10) of different Districts of the State in order to justify the issuance of the notification. CW 2, Smt. L. Kharkongor, Deputy Commissioner, Jaintia Hills District, Jowai, had in her examination-in-chief stated as under :—

“I am the Deputy Commissioner of Jaintia Hills District, Jowai, Meghalaya. I joined as Deputy Commissioner of this area on 19-5-2003. I have gone through the affidavit filed by Smt. R.V. Suchiang, IAS,

Commissioner and Secretary to Government of Meghalaya, Political Department and also the documents (Exhibits CW1/1 to CW1/19) filed therewith. In my district Hynniewtre National Liberation Council (For short 'HNLC') is more active than the Achik National Volunteer Council (for short 'ANVC') in their unlawful activities. The main objective of these organizations is to have Meghalaya declared as an independent State and not to be an integral part of Union of India. There are number of incidents relating to these organizations that have occurred in the territory under my jurisdiction during my tenure. Out of these, at least 9-10 matters are forwarded to the Courts of competent jurisdiction, but in some charge sheets have not been filed and in others investigations have not been completed. As there is a fear amongst common public in regard to these organizations, that is why more incidents occur than the ones, which are brought to the notice of the authorities and ultimately cases are registered. 10 to 15 members of these organizations have been arrested in my area. The offences committed by these organisations relate to extortion, kidnapping, murder and other allied offences. Jimmi Summer and Emlang Sutnga are the members of these organisations who have been arrested. They have been arrested in Khliehriat PS case No. 92(11) 03 under Section 25(b) (A)(1B) and 27 Arms Act and in extortion case being Jowai PS case No. 14(1) 2005 under Section 384/511/120(b)/121 IPC read with Sections 10 and 13 of the Unlawful Activities (Prevention) Act and in Khliehriat PS case No. 7(1) 05 under Section 395/397 IPC read with Section 27 Arms Act respectively. In January 2005, there was a case of Bank robbery in my jurisdiction which took place in Meghalaya Cooperative Apex Bank, Khliehriat Branch. Emlang Sutnga, who is one of the members of the gang was arrested for committing robbery and he is closely associated with the unlawful activities of HNLC. There have been recovery of arms and ammunition from the members of these organizations who have been arrested from time to time. The recovery include AK-47 rifles and some other ammunitions. In Jaintia Hills District, there are coal mines and business class People which are affluent reside in that area. This affluent class is one of the main target of these organizations from whom they try to extract money. These organizations have connections with the other banned organizations particularly National Socialistic Council of Nagalim (IM). The activities of these unlawful organizations, more particularly, in conspiracy with the other banned organisations, cause a serious threat to the sovereignty, integrity and internal and external security of India."

The Deputy Commissioners of other districts had also made similar statements and had even referred to incidents, crimes and unlawful activities carried out by ANVC and HNLC within their jurisdiction. They have specifically referred to the documents, Ex. CW 1/1 to CW 1/19 in support of their statements. Similarly, Sh. A.S. Rynjah, Superintendent of Police, East Khasi Hills District, Shillong, was examined as CW5 and his examination-in-chief reads as under :—

"I am presently working as Superintendent of Police, East Khasi Hills District, Shillong. I was posted in this District on 27th October, 2003. I have gone through the affidavit filed by Ms. R.V. Suchiang, IAS, Commissioner and Secretary to Govt. of Meghalaya, Political Department and also the documents (Exhibits CW 1/1 to CW 1/19) filed therewith. They are correct copies of the record. The unlawful activities/crimes which are being committed by unlawful organizations, namely, Achik National Volunteer Council (ANVC) and Hynniewtre National Liberation Council (HNLC) pertaining to my jurisdiction have been mentioned in these annexures.

Out of the two abovementioned unlawful organizations, Hynniewtre National Liberation Council is more active. Shillong, the capital of State of Meghalaya, is part of my jurisdiction. The main object of these two unlawful organizations is to form separate States 'Garo Land' and 'Khasi Hills', which will not be part of Union of India.

During the year 2003, there were 27 cases registered with various Police Stations in my jurisdiction while in the year 2004, 3 cases have been registered.

One of the most important incident of serious consequences which I wish to state before the Tribunal is as under :—

"On Sep. 16, 2004, Police arrested one HNLC cadre, namely, Shanbor Warjri @ Bah Duh Shi, from Mawlai Mawdatbaki, Shillong. One 9mm Pistol, loaded with 8 rds. of live ammunition was seized from his possession. On his leading one AK Assault Rifle, five magazines and 107 rds. of live AK ammunition were recovered from a house at Mawlai Umjaiur, Shillong. This refers to Mawlai PS Case No. 44(9)04 u/s 25(1-a)/27 Arms Act r/w Sec. 10/13 UA(P) Act.

I further state that the person who was arrested belongs to the higher cadre of Hynniewtre National Liberation Council and was sent by the senior most persons of the organization whose headquarters is in Bangladesh and was sent to Shillong with twin aims. One aim was to achieve the object of separate State while the other was for eliminating the members of HNLC who had betrayed their trust in the past. They wanted to achieve these two goals through armed struggle."

Fund collection is also one of their main aims which is achieved by extortion, causing fear in the minds of people and ensuring that they pay up as and when demands were made. There have been a number of encounters with the terrorists but during my tenure there have been no casualties of the police officers. Earlier to that, there have been some incidents of casualties of police officials. On different occasions, large number of ammunition and weapons have been recovered from the arrest of the members of these two unlawful organizations. The recoveries made from them include AK-47 rifles, 9 mm pistols and huge ammunition. Some of the incidents where the members of these two organizations attacked, and in fact also attacked the various police stations under my jurisdiction, are as under :—

“12/8/2003 : Suspected HNLC militants threw a hand grenade at Mawlai PS compound. In the incident Const., 147 Fieldstone Sangma received serious injury on his chest. [Mawlai PS Case No. 38(8)03 u/s 3 IES Act r/w Sec. 353 IPC and Sec. 10/13 UA(P) Act.]

14/08/2003 : Suspected HNLC militants attempted to lob a hand grenade at Lumdiengjri PS, the grenade exploded on the road near the PS. [Lumdiengjri PS Case No. 125(8)03 u/s 307/34 IPC r/w 3 IES Act and Secs. 10/13 UA(P) Act.]

16/08/2003 : Suspected HNLC militants hurled a hand grenade at PTS, Mawlai Mawroh, Shillong. The grenade exploded near the office building, damaging window panes and partial damage to the wall of the building [Sadar PS Case No. 233(8) 03 u/s 307/34 IPC r/w Sec. 5 IES Act and Sec. 10/13 UA(P) Act.]”

Some incidents or crimes committed by the members of these organizations are not even reported because of fear. However, in my district I have been able to reduce the terrorist activities. Business community is the main target of these organisations as these organizations can easily extort money from them. These unlawful organizations have direct links with other banned unlawful organizations including National Socialist Council of Nagalim (Issac Muivah) and NLFT.

HNLC get training and support from the above mentioned unlawful organizations. The nexus between these unlawful organizations is very strong one and their intention is to disturb the peaceful living in this State as well as to cause threat to national security.

The activities of these unlawful organizations, more particularly in conspiracy with the other banned organizations cause a serious threat to the sovereignty, integrity and internal and external security of India.”

The other police officers who were examined as CW-6 to CW-10 had also made similar statements and referred to certain heinous crimes, unlawful activities carried out by HNLC and ANVC within the area of their jurisdiction. They specifically referred to and relied upon Ex. CW 1/1 to CW 1/19 in support of their statements. As already noticed all these witnesses with their respective records were offered for cross-examination and as nobody was there to cross-examine them, they were discharged. Mr. R. R. Jha, who was examined as CW-11 was also tendered for cross-examination and his affidavit along with the annexures, was exhibited as Ex. CW11/A. From the above detailed evidence led on behalf of the Central Government as well as the State of Meghalaya, it is clear that these associations are indulging in unlawful activities and besides being involved in heinous crimes have caused fear psychosis in the minds of the general public which obviously disrupts the administration of the State. HNLC has demonstrably asserted its objective of asking for an independent State by secession of Meghalaya from India. ANVC has been carrying out various unlawful activities including the crime of extortion, murder, abduction and raising violence against the State Administration and security forces.

The definition of unlawful activities under Section 2(o) of the Act was amended so as to incorporate (i), (ii) and (iii) and by addition of the expression ‘or’. The amendment of this definition clause has significantly changed the scope of the expression ‘unlawful activity’. In the pre-amended definition clause, both the ingredients of (i) and (ii) ought to be satisfied, while under the amended clause, in the event either of the three clauses mentioned under Sub-section (o) of Section 2 are satisfied, it would be an ‘unlawful activity’. “Any individual or association” “which causes or is intended to cause disaffection against India”, would be an “Individual” or an “association” involved in an unlawful activity. “Disaffection” has been explained to be including disloyalty and all feelings of enmity. It is the species of disaffection and people are disaffected to the Government. In simple words, it is a manner of challenging the administration by unlawful means. In giving this expression a wide meaning, a Bench of Calcutta High Court in the case of “*Saptaha*” a Bengali B-Weekly Newspaper and in the matter of Benoy Kumar Chattopadhyaya AIR 1950 Calcutta 445 held as under :—

“The word ‘disaffection’ signifies political alienation or discontent, that is to say, a feeling of disloyalty to the existing Government, which tends to a disposition not to obey, but to resist and subvert the Government.”

Section 2(p) defines ‘unlawful association’ as any association “which has for its object any unlawful activity, or which encourages or aids persons to undertake any unlawful activity, or of which the members undertake such activity”.

The Legislature intended to give this defining sub-section a wider meaning and interpretation, that is the precise reason as to why words like “encourages”, “aids” have been used in the Section. Even if an association has for its objective any activity which is punishable under Section 153A or 153B of the Indian Penal Code, or the members of which undertake such activity, would be an ‘unlawful association’. There is no occasion for the Tribunal to give it a restricted interpretation/meaning. In any case, the afore-noticed activities of these two associations ANVC and HNLC are an open challenge to the sovereign power of the State, their unlawful activities including causing fear psychosis in the minds of the public, by extortion of money, abduction, murder and attack on security forces are the clear indications of the attempt on the part of these associations to hinder the State Administration by unlawful and illegal means. These associations are actually still involved in procuring of weapons, infringing the borders of the Union of India, keeping their contacts with other banned organisations and unlawful associations in and outside the territorial limits of Indian Territory.

In the case of Union of India and Ors. Vs. Sukumar Sengupta and Ors., 1990 (supp) Supreme Court Cases 545 sovereignty was described by the Court as a quality of right, a bundle of rights and that it depends on the facts and circumstances of each case. The complexities of modern developed societies need amicable and peaceful settlement of national and international disputes and the expression sovereignty and independence had to be modified, keeping in view the developments. It being a bundle of rights, obligation of the State to protect members of its Society is placed on a higher pedestal. Casual principles of settled law thus, require the interpretation of unlawful assemblies and unlawful activities in that direction. If the members of these unlawful associations are terrorising the common man on the road and create a law and order problem for normal administration by the different State organs with the aims aforesaid, would not only be intending but actually disrupting the sovereignty and territorial integrity of India.

Explaining the importance of the concept of sovereignty, the Supreme Court in the case of Synthetics and Chemicals Ltd. and Ors. Vs. State of U.P. and Ors., (1990) 1 Supreme Court Cases 109, held that “it is the exercise of sovereign power which gives the State sufficient authority to enact any law subject to the limitations of the Constitution to discharge its functions. The Indian State, between the Centre and the States, has sovereign power. The sovereign power is plenary and inherent in every sovereign State to do all things which promote the health, peace, morals, education and good order of the people! This power of sovereignty is, however, subject to Constitutional Limitations.”

The above enunciated principles of law indicate that the expression “sovereignty” is to be given a meaning which is understood in common parlance and is certainly an expression of wide dimensions. The object of power of sovereignty is ultimately for the welfare of the people of the State. So to perform its functions of that kind without disruption, unlawful impediments and threat from an association or a group of persons would infringe the very basic fundamentals of democratic system.

There is definite documentary, oral and specialized evidence on record to show that these unlawful associations are involved in unlawful activities within the contemplation of the provisions of the Act. The unlawful activities of these unlawful associations are not mere intent but are actually activities to cause threat to the sovereignty of State, Union of India and main object of HNLC is to claim secession of Meghalaya from Union of India by carving out an independent State in terms of their demand. Apparent consequences of their aforesaid unlawful activities would be threat and disruption of the sovereignty and territorial integrity of India. The State and Central Government have fully discharged their onus to substantiate their prayer before the Tribunal that there is sufficient cause for declaring these associations as unlawful.

In view of my above detailed discussion, I am of the considered view that sufficient cause exists for declaring ANVC and HNLC as ‘unlawful associations’. Thus, I pass an order in terms of Section 4, sub-section (3) confirming the notification dated 16th November, 2004 issued by the Central Government under Section 3(1) of the Act.

May 12, 2005

Sd/-  
(SWATANTER KUMAR)  
Presiding Officer,  
The Unlawful Activities (Prevention) Tribunal  
[F.No. 11011/47/2004-NE.III]  
RAJIV AGARWAL, Jt. Secy.